Sl.No. 28 (1)

F.No.3-38/2006-AR(PF-I)
अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
Andaman and Nicobar Administration
सचिवालय / **Secretariat**
****

Port Blair dated the 28th May, 2008.

Copies of letter No.13/10/2007-IR dated 29/04/08, letter No.1/3/2008-IR dated 25/04/08 and letter No.1/4/2008-IR dated 25/04/08 received from Shri.K.G.Verma, Director, Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, New Delhi regarding Guidelines for the designated PIO, APIO and First Appellate Authority and Public Authorities under the RTI Act,2005 are enclosed herewith with the request that the contents of the above said Guidelines may be brought to the notice of the designated/appointed PIOs, APIOs in their respective departments to ensure implementation of the provisions of the RTI Act, 2005

1. All HODs (Copy enclosed)
2. General Manager, ANIIDCO
3. Managing Director,
   A&N Forest Plantation Development Corporation Ltd.,
4. All Assistant Secretaries,
   A&N Administration,
   Port Blair.

15/5/08
Assistant Secretary (AR)

15/5/08

No.13/10/2007-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
....

North Block, New Delhi
Dated: the 29th April, 2008

To

1. Central Information Commission,
August Kranti Bhawan,
Bhikaji Cama Place,
New Delhi
2. All the State Information Commissions

Subject: Special Civil Application No.23305 of 2007 – Ahmedabad Education Society & Another Vs. UOI & Ors.
****

Sir,

I am directed to bring following observations made by the High Court of Gujarat in the matter of Ahmedabad Education Society & Another V/s UOI & Others [Special Civil Application No.23305 of 2007] to the notice of the Central Information Commission and all the State Information Commissions:

"As per Section 18, the complaint can be preferred before the State Information Commission and Chief Information Commissioner can initiate an inquiry and can impose penalty as per Section 20 of the Act, 2005. While holding inquiry, as per Section 18(3) of the Act, 2005, State Chief Information Commissioner has been clothed with powers of the Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of summoning and enforcing the attendance of persons and compel them to give oral and written evidence on oath, requiring the discovery and inspection of documents; receiving evidence on affidavit; requisitioning any public record or copies thereof from any court or office. But so far as refund of fees is concerned, it is a mater to be decided by the Civil Court of competent jurisdiction under Code of Civil Procedure, 1907.

State Chief Information Commissioner has no power, jurisdiction and authority under the Act, 2005, to pass an order of refund of the fees."

Yours faithfully,

(K.G. Verma)
Director
Tele: 23092158

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs

संख्या-13/10/2007-आईआर

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 29 अप्रैल, 2008

सेवा में,

1. केन्द्रीय सूचना आयोग,
   अगस्त क्रांति भवन,
   भीकाजी कामा प्लेस,
   नई दिल्ली ।

2. सभी राज्य सूचना आयोग ।

विषय: विशेष सिविल आवेदन संख्या 2007 का 23305 – अहमदाबाद एजुकेशन सोसायटी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य ।

****

महोदय,

मुझे अहमदाबाद एजुकेशन सोसायटी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य [विशेष सिविल आवेदन संख्या 2007 का 23305] के मामले में गुजरात के उच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को केन्द्रीय सूचना आयोग और सभी राज्य सूचना आयोगों के ध्यान में लाने का निदेश हुआ है:

> "धारा 18 के अनुसार राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है और मुख्य सूचना आयुक्त जाँच-पड़ताल आरम्भ कर सकता है और अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अनुसार शास्ति लगा सकता है । जांच-पड़ताल करते समय, अधिनियम की धारा 18(3) के अनुसार, दस्तावेजों की खोज और जांच की आवश्यकता होने पर व्यक्तियों को बुलाने और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने

157

और उनको शपथ के साथ मौखिक औरि लिखित साक्ष्य देने हेतु बाध्य करने, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने, किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक अभिलेख अथवा इसकी प्रतियां मांगने के सम्बन्ध में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं । लेकिन अब तक, जहां तक शुल्क की वापसी का सम्बन्ध है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1907 के अंतर्गत सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना वाला विषय है । राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, शुल्क वापसी का आदेश जारी करने की कोई भी शक्ति, क्षेत्राधिकार अथवा प्राधिकार प्राप्त नहीं है ।"

भवदीर

(के.जी. वर्म

निदेशक

दूरभाष: 2309215

प्रति: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।